Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2026: 8.739,
https://www.srjis.com/issues_data/291
PEER REVIEWED, REFEREED & INDEXED JOURNAL, APRIL-MAY 2026, VOL-14/75

नैतिक मूल्य एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : समकालीन परिप्रेक्ष्य में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ0 सुशील कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, बी.एड्. विभाग स्वामी देवानन्द पी.जी. कालेज, मठ–लार देवरिया
डॉ0 अवधेश कुमार चौधरी
असिस्टेंट प्रोफेसर, बी.एड्. विभाग लाल बहादुर भाास्त्री स्मारक पी.जी. कालेज, आनन्दनगर, महराजगंज

Paper Received On: 21 APRIL 2026
Peer Reviewed On: 25 MAY 2026
Published On: 01 JUNE 2026

Abstract

शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन एवं व्यावसायिक दक्षताओं का विकास करना नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व के नैतिक, सामाजिक एवं मानवीय पक्षों का संवर्धन करना भी है। वैश्वीकरण, तकनीकी विस्तार एवं तीव्र सामाजिक परिवर्तन के वर्तमान दौर में नैतिक मूल्यों का प्रश्न पुनः शिक्षा विमर्श के केंद्र में उभरकर सामने आया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा, उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों तथा सामाजिक विघटन की परिस्थितियों में ऐसी शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, जो विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व, सहिष्णुता, करुणा, सत्यनिष्ठा तथा संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता विकसित कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन का दृष्टिपत्र है। यह नीति समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा की अवधारणा को स्वीकार करते हुए नैतिक एवं मानवीय मूल्यों को शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग मानती है। नीति में संवैधानिक कर्तव्यों, भारतीय ज्ञान परंपरा, वैश्विक नागरिकता, सेवा–भाव, पर्यावरणीय चेतना तथा नैतिक निर्णय क्षमता के विकास पर विशेष बल दिया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य नैतिक मूल्यों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मध्य अंतर्संबंध का विश्लेषण करना है। अध्ययन में नैतिक मूल्यों की अवधारणा, नीति के प्रमुख प्रावधानों, भारतीय संदर्भ में नैतिक शिक्षा की स्थिति, समक्ष उपस्थित चुनौतियों तथा संभावित नीतिगत उपायों का परीक्षण किया गया है। अध्ययन से यह प्रतिपादित होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन शिक्षा को अधिक मानवीय, उत्तरदायी एवं मूल्यपरक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकता है।

मुख्य शब्द : *नैतिक मूल्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मूल्य शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा, संवैधानिक मूल्य, समग्र शिक्षा, चरित्र निर्माण, नैतिक विकास, शिक्षा नीति।*

प्रस्तावना–

शिक्षा किसी भी समाज के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास की आधारशिला मानी जाती है। यह केवल सूचना एवं कौशल के हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि व्यक्ति के दृष्टिकोण, व्यवहार एवं जीवन–मूल्यों को आकार देने का एक प्रभावी माध्यम भी है। इतिहास साक्षी है कि जिन समाजों ने शिक्षा को नैतिकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ा, उन्होंने दीर्घकालिक एवं संतुलित विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की। इसके विपरीत, जब शिक्षा का स्वरूप केवल रोजगार एवं आर्थिक उपलब्धियों तक सीमित हो जाता है, तब सामाजिक जीवन में असंतुलन एवं मूल्य–संकट की स्थितियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। समकालीन समाज अनेक जटिल चुनौतियों का सामना कर रहा है। हिंसा, असहिष्णुता, भ्रष्टाचार, सामाजिक विभाजन तथा डिजिटल माध्यमों के दुरुपयोग जैसी समस्याओं ने नैतिक शिक्षा की आवश्यकता को और अधिक प्रासंगिक बना दिया है। विशेष रूप से युवा पीढ़ी के समक्ष ऐसे अनेक विकल्प एवं प्रभाव उपस्थित हैं, जो उनके निर्णयों एवं व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा संस्थानों की भूमिका केवल ज्ञान प्रदाता के रूप में नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण के केंद्र के रूप में भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय चिंतन परंपरा में शिक्षा और नैतिकता का संबंध अत्यंत प्राचीन है। उपनिषदों, बौद्ध साहित्य तथा महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद एवं रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे चिंतकों ने शिक्षा को आत्मानुशासन, सेवा एवं मानव कल्याण के साथ जोड़कर देखा है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विकासक्रम में समय–समय पर विभिन्न आयोगों एवं नीतियों ने मूल्य–आधारित शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है। कोठारी आयोग (1964–66) ने भी शिक्षा को राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन माना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी व्यापक परंपरा एवं समकालीन आवश्यकताओं के मध्य एक सेतु के रूप में

Copyright@2026 Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

उभरकर सामने आती है। यह नीति शिक्षा को समग्र, समावेशी एवं बहुविषयक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास करती है। साथ ही, इसमें संवैधानिक मूल्यों, कर्तव्यों, नैतिक चेतना एवं सामाजिक सहभागिता के विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नीति का दृष्टिकोण यह है कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना होना चाहिए, जो ज्ञानवान होने के साथ–साथ संवेदनशील, उत्तरदायी एवं नैतिक दृष्टि से परिपक्व भी हों। प्रस्तुत शोध पत्र में नैतिक मूल्यों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्संबंध का विश्लेषण किया गया है।

नैतिक मूल्यों की अवधारणा–

नैतिक मूल्य मानव व्यवहार को दिशा प्रदान करने वाले वे मानदंड हैं, जो व्यक्ति को उचित एवं अनुचित, न्याय एवं अन्याय तथा कर्तव्य एवं अधिकार के मध्य विवेकपूर्ण अंतर करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये मूल्य किसी समाज की सांस्कृतिक परंपराओं, दार्शनिक मान्यताओं तथा सामूहिक अनुभवों से निर्मित होते हैं और समय के साथ सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग के रूप में विकसित होते हैं। सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, करुणा, सहिष्णुता, उत्तरदायित्व, अनुशासन एवं परोपकार जैसे तत्व नैतिक मूल्यों के प्रमुख घटक माने जाते हैं। नैतिक मूल्यों की अवधारणा का संबंध केवल व्यक्तिगत आचरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संबंधों एवं सामुदायिक जीवन से भी गहराई से जुड़ी हुई है। व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में जो निर्णय लेता है, वे न केवल उसके व्यक्तिगत चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं, बल्कि समाज की नैतिक संरचना को भी प्रभावित करते हैं। इस दृष्टि से नैतिक मूल्य सामाजिक सामंजस्य, पारस्परिक विश्वास एवं सहयोग की भावना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण से नैतिकता का अध्ययन प्राचीन काल से ही विचार का विषय रहा है। भारतीय दर्शन में धर्म, कर्तव्य एवं सदाचार को मानव जीवन के आवश्यक तत्वों के रूप में स्वीकार किया गया है। उपनिषदों में सत्य एवं आत्मानुशासन को जीवन का आधार माना गया है, जबकि बौद्ध दर्शन करुणा एवं मध्यम मार्ग पर बल देता है। इसी प्रकार, जैन दर्शन अहिंसा एवं अपरिग्रह को नैतिक जीवन का मूल आधार मानता है। पाश्चात्य चिंतन में अरस्तू ने सद्गुण (Virtue) को नैतिक जीवन का केंद्र माना, जबकि इमैनुएल कांट ने नैतिक कर्तव्य एवं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की अवधारणा प्रस्तुत की। नैतिक मूल्यों का विकास एक सतत प्रक्रिया है, जो परिवार, विद्यालय, समुदाय एवं व्यापक सामाजिक परिवेश के संयुक्त प्रभाव से संपन्न होती है। बाल्यावस्था में प्राप्त अनुभव व्यक्ति के नैतिक दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित करते हैं। परिवार प्रारंभिक सामाजिककरण का माध्यम है, जहाँ बालक सत्यनिष्ठा, अनुशासन एवं पारस्परिक सम्मान जैसे गुणों को सीखता है। इसके पश्चात विद्यालय इन मूल्यों को व्यवस्थित एवं संस्थागत स्वरूप प्रदान करता है। शिक्षकों का आचरण, सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया तथा विद्यालयी संस्कृति नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। समकालीन समाज में नैतिक मूल्यों का प्रश्न नई चुनौतियों के साथ उभरकर सामने आया है। तकनीकी प्रगति एवं डिजिटल माध्यमों के विस्तार ने सूचना तक पहुँच को सरल बनाया है, किंतु इसके साथ ही आभासी पहचान, साइबर दुरुपयोग एवं सामाजिक अलगाव जैसी स्थितियों में भी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, उपभोक्तावादी संस्कृति एवं तीव्र प्रतिस्पर्धा ने अनेक बार व्यक्तिगत सफलता को सामाजिक उत्तरदायित्व से अधिक महत्व प्रदान किया है। ऐसी परिस्थितियों में नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि वे व्यक्ति को संतुलित एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षा के संदर्भ में नैतिक मूल्यों का महत्व विशेष रूप से स्वीकार किया गया है। मूल्य–आधारित शिक्षा विद्यार्थियों में केवल ज्ञान का विकास नहीं करती, बल्कि उनमें आत्मानुशासन, नेतृत्व, सहानुभूति एवं सामाजिक प्रतिबद्धता जैसे गुणों का भी संवर्धन करती है। इसके माध्यम से ऐसे नागरिकों का निर्माण संभव होता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों एवं सामाजिक न्याय के प्रति सजग हों। इस प्रकार, नैतिक मूल्य शिक्षा के मानवीय आयाम को सुदृढ़ करते हैं तथा समाज में उत्तरदायी नागरिकता की स्थापना में योगदान देते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : एक परिचय–

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक एवं संरचनात्मक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। लगभग तीन दशकों के अंतराल के पश्चात प्रस्तुत की गई इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, बहुविषयक, लचीला एवं भविष्य उन्मुख बनाना है। यह नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना प्रस्तुत करती है, जो ज्ञान, कौशल, नैतिकता एवं नवाचार के मध्य संतुलन स्थापित कर सके।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति के निर्माण में व्यापक परामर्श प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें शिक्षकों, शिक्षाविदों, नीति–निर्माताओं, अभिभावकों एवं विभिन्न हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित की गई। नीति का मूल उद्देश्य भारत को एक ज्ञान–आधारित समाज एवं वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में विकसित करना है। इसके लिए शिक्षा को केवल परीक्षा–केंद्रित दृष्टिकोण से मुक्त कर अनुभवात्मक, विश्लेषणात्मक एवं शिक्षार्थी–केंद्रित स्वरूप प्रदान करने पर बल दिया गया है।

- नीति की एक प्रमुख विशेषता विद्यालयी शिक्षा की संरचना में परिवर्तन है। पारंपरिक 10+2 व्यवस्था के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल को अपनाया गया है, जो बालकों के संज्ञानात्मक एवं मनोवैज्ञानिक विकास के विभिन्न चरणों को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया है। यह संरचना प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ते हुए अधिगम की निरंतरता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी नीति ने अनेक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए हैं। बहुविषयक विश्वविद्यालयों की स्थापना, शैक्षणिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC), बहु–प्रवेश एवं बहु–निकास प्रणाली तथा अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (National Research Foundation) की स्थापना जैसे प्रावधान शिक्षा को अधिक लचीला एवं नवाचारोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसके अतिरिक्त, नीति उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) को वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत तक पहुँचाने का लक्ष्य भी निर्धारित करती है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक विशिष्ट पक्ष इसका समग्र शिक्षा पर बल देना है। नीति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं सृजनात्मक विकास को भी सुनिश्चित करना है। इसी कारण नीति में कला, खेल, व्यावसायिक शिक्षा एवं जीवन–कौशल को शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना गया है।
- भारतीय ज्ञान परंपरा, संवैधानिक मूल्यों एवं बहुभाषिकता को भी नीति में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। नीति विद्यार्थियों में कर्तव्य–बोध, सहानुभूति, विविधता के प्रति सम्मान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर बल देती है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरणीय चेतना, सतत विकास एवं वैश्विक नागरिकता जैसे विषयों को भी शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया गया है। यह दृष्टिकोण शिक्षा को स्थानीय संदर्भों एवं वैश्विक आवश्यकताओं के मध्य संतुलित बनाने का प्रयास करता है।
- प्रौद्योगिकी के उपयोग के संदर्भ में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। डिजिटल शिक्षण, ऑनलाइन अधिगम एवं प्रौद्योगिकी–सक्षम शैक्षिक संसाधनों के विकास पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही, यह भी स्वीकार किया गया है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय मूल्यों एवं शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार, नीति तकनीकी प्रगति एवं मानवीय संवेदनाओं के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है।

संक्षेप में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था के पुनर्संरचनात्मक परिवर्तन का एक व्यापक दृष्टिपत्र है। इसकी विशेषता यह है कि यह शिक्षा को ज्ञान, कौशल एवं नैतिकता के समन्वित स्वरूप में प्रस्तुत करती है तथा ऐसे नागरिकों के निर्माण की परिकल्पना करती है, जो बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भी अपने सामाजिक एवं नैतिक दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध रहें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नैतिक मूल्यों का स्थान–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को केवल ज्ञान एवं कौशल अर्जन की प्रक्रिया के रूप में नहीं देखती, बल्कि इसे व्यक्ति के समग्र विकास का माध्यम मानती है। इसी कारण नीति के विभिन्न प्रावधानों में नैतिक मूल्यों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से समाहित किया गया है। नीति का दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों की बौद्धिक क्षमता के साथ–साथ उनके नैतिक एवं सामाजिक दायित्व–बोध पर भी निर्भर करती है। अतः शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना होना चाहिए, जो अपने अधिकारों के साथ–साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संवैधानिक मूल्यों को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। नीति में यह अपेक्षा व्यक्त की गई है कि शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों में लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के आदर्शों के प्रति सम्मान विकसित किया जाए। इसके अतिरिक्त, नीति विविधता में एकता, राष्ट्रीय एकीकरण एवं सामाजिक समरसता जैसे मूल्यों को भी शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों के रूप में स्वीकार करती है। यह दृष्टिकोण विद्यार्थियों को उत्तरदायी एवं सक्रिय नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करता है। नीति में चरित्र निर्माण को शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित किया गया है। सत्यनिष्ठा, सहानुभूति, सहयोग, अनुशासन एवं सेवा–भाव जैसे गुणों को शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाने पर बल दिया गया है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि नीति विद्यार्थियों को केवल शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास के आधार पर भी देखने की वकालत करती है। इससे शिक्षा का स्वरूप अधिक मानवीय एवं संतुलित बनता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेशन के माध्यम से भी नीति नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का प्रयास करती है। प्राचीन भारतीय चिंतन में निहित जीवन–दृष्टि, कर्तव्य–बोध, सहअस्तित्व एवं लोककल्याण की अवधारणाओं को समकालीन शिक्षा के साथ जोड़ने की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य अतीत की पुनरावृत्ति करना नहीं, बल्कि उन सार्वकालिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करना है, जो वर्तमान समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रासंगिक हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को भी नैतिकता के एक

महत्वपूर्ण आयाम के रूप में स्वीकार करती है। नीति में सतत विकास, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं पर्यावरणीय चेतना के विकास पर बल दिया गया है। इससे विद्यार्थियों में यह समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है कि मानव एवं प्रकृति के मध्य संबंध परस्पर निर्भरता पर आधारित हैं। इस प्रकार, पर्यावरणीय नैतिकता को शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों के साथ जोड़ा गया है। वैश्विक नागरिकता की अवधारणा भी नीति में नैतिक मूल्यों की उपस्थिति को रेखांकित करती है। वर्तमान समय में समाज एवं अर्थव्यवस्था की वैश्विक प्रकृति को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि विद्यार्थी विभिन्न संस्कृतियों, दृष्टिकोणों एवं मानवीय अनुभवों के प्रति सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस आवश्यकता को स्वीकार करते हुए ऐसे नागरिकों के निर्माण की परिकल्पना करती है, जो स्थानीय पहचान को बनाए रखते हुए वैश्विक स्तर पर उत्तरदायी भूमिका निभाने में सक्षम हों। इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नैतिक मूल्यों को किसी पृथक विषय या पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के मूलभूत तत्व के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यही विशेषता इस नीति को पूर्ववर्ती नीतियों से पृथक एवं अधिक समग्र बनाती है।

नैतिक मूल्यों के विकास हेतु नीति के प्रमुख प्रावधान–

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनेक ऐसे प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों में नैतिक, सामाजिक एवं मानवीय गुणों का विकास करना है। ये प्रावधान पाठ्यचर्या, शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन प्रणाली एवं संस्थागत संस्कृति जैसे विविध आयामों से संबंधित हैं। नीति का दृष्टिकोण यह है कि नैतिक मूल्यों का विकास केवल सैद्धांतिक शिक्षण से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए अनुभवात्मक एवं सहभागितापूर्ण अधिगम की आवश्यकता होती है।
- प्रथम, नीति समग्र एवं बहुआयामी शिक्षा पर बल देती है। इसके अंतर्गत कला, संगीत, खेल, साहित्य एवं सामुदायिक गतिविधियों को शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाया गया है। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में सहयोग, नेतृत्व, आत्मानुशासन एवं पारस्परिक सम्मान जैसे गुणों का विकास संभव होता है। इस प्रकार, पाठ्यचर्या को अधिक व्यापक एवं जीवनोपयोगी स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया है।
- द्वितीय, अनुभवात्मक अधिगम (Experiential Learning) को नीति में विशेष महत्व दिया गया है। परियोजना–आधारित शिक्षण, समूह कार्य, क्षेत्रीय भ्रमण एवं सामुदायिक सहभागिता जैसी गतिविधियाँ विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ती हैं। इन अनुभवों के माध्यम से उनमें संवेदनशीलता, समस्या–समाधान क्षमता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास होता है। इससे नैतिक मूल्यों को व्यवहारिक संदर्भ प्राप्त होता है।
- तृतीय, नीति में सेवा–भाव एवं सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों को स्थानीय समुदायों के साथ कार्य करने, सामाजिक समस्याओं को समझने एवं उनके समाधान में योगदान देने के अवसर प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। यह दृष्टिकोण शिक्षा को कक्षा–कक्ष की सीमाओं से बाहर ले जाकर समाज से जोड़ता है तथा नागरिक उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करता है।
- चतुर्थ, मातृभाषा एवं भारतीय भाषाओं के उपयोग पर बल भी नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह किसी समाज की सांस्कृतिक स्मृति एवं जीवन–दृष्टि को भी अभिव्यक्त करती है। नीति के इस प्रावधान से विद्यार्थियों में अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान एवं आत्मबोध का विकास संभव हो सकता है।
- पंचम, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार भी नैतिक शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रटने पर आधारित परीक्षाओं के स्थान पर योग्यता, विश्लेषणात्मक क्षमता एवं रचनात्मक चिंतन पर आधारित मूल्यांकन की वकालत करती है। इससे विद्यार्थियों पर अनावश्यक प्रतिस्पर्धात्मक दबाव में कमी आती है तथा वे सीखने की प्रक्रिया को अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से ग्रहण कर पाते हैं। यह परिवर्तन शिक्षा को अधिक सहयोगात्मक एवं मानवीय बनाने की दिशा में सहायक हो सकता है।
- षष्ठम, शिक्षक की भूमिका को नीति में पुनर्परिभाषित किया गया है। शिक्षक को केवल ज्ञान प्रदाता न मानकर मार्गदर्शक, प्रेरक एवं आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखा गया है। नैतिक मूल्यों का प्रभावी संप्रेषण तभी संभव है, जब शिक्षक स्वयं अपने आचरण एवं व्यवहार के माध्यम से उन मूल्यों का उदाहरण प्रस्तुत करें। इस कारण नीति शिक्षक–प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास को भी विशेष महत्व प्रदान करती है।
- सप्तम, विद्यालयी संस्कृति एवं संस्थागत वातावरण को भी नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। यदि शैक्षणिक संस्थानों में समानता, सम्मान, संवाद एवं सहभागिता की संस्कृति विद्यमान हो, तो विद्यार्थियों में इन मूल्यों का स्वाभाविक विकास होता है। अतः नीति एक ऐसे शैक्षिक वातावरण की परिकल्पना करती है, जहाँ अधिगम के साथ–साथ मानवीय संबंधों को भी महत्व प्राप्त हो।

अंततः, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ये प्रावधान यह संकेत करते हैं कि नैतिक मूल्यों का विकास शिक्षा का सहायक उद्देश्य नहीं, बल्कि उसका केंद्रीय तत्व है। इन प्रावधानों का प्रभावी एवं सतत क्रियान्वयन शिक्षा को अधिक उत्तरदायी, समावेशी एवं मूल्य–आधारित स्वरूप प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में नैतिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति–

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में नैतिक शिक्षा की अवधारणा नवीन नहीं है। प्राचीन गुरुकुल परंपरा से लेकर आधुनिक शिक्षा प्रणाली तक, विभिन्न रूपों में नैतिक एवं चारित्रिक विकास को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में सम्मिलित किया जाता रहा है। तथापि, समय के साथ शिक्षा के उद्देश्यों, सामाजिक संरचना एवं आर्थिक प्राथमिकताओं में हुए परिवर्तनों ने नैतिक शिक्षा के स्वरूप एवं उसकी प्रभावशीलता को प्रभावित किया है। वर्तमान भारतीय संदर्भ में नैतिक शिक्षा अनेक अवसरों एवं चुनौतियों के मध्य विकसित हो रही है।

- **विद्यालयी शिक्षा** के स्तर पर विभिन्न राज्य शिक्षा बोर्डों एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने मूल्य–आधारित शिक्षा से संबंधित विषयों एवं गतिविधियों को पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया है। प्रार्थना सभाएँ, सामुदायिक सेवा कार्यक्रम, पर्यावरण जागरूकता अभियान एवं सह–पाठ्यक्रम गतिविधियाँ विद्यार्थियों में सामाजिक एवं नैतिक चेतना के विकास के उद्देश्य से संचालित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, NCERT द्वारा विकसित पाठ्यपुस्तकों में भी लोकतांत्रिक मूल्यों, लैंगिक समानता एवं सामाजिक समावेशन जैसे विषयों को स्थान प्रदान किया गया है।
- **उच्च शिक्षा** के क्षेत्र में भी नैतिक शिक्षा को विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं संस्थागत पहलों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मानव मूल्य एवं व्यावसायिक नैतिकता (Human Values and Professional Ethics) जैसे पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) तथा युवा कार्यक्रम विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व एवं सामाजिक सहभागिता की भावना विकसित करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। इन पहलों ने शिक्षा को सामाजिक दायित्वों के साथ जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बावजूद, नैतिक शिक्षा के व्यावहारिक पक्ष के संबंध में अनेक प्रश्न विद्यमान हैं। अनेक शैक्षणिक संस्थानों में नैतिक मूल्यों का शिक्षण औपचारिक एवं परीक्षा–केंद्रित गतिविधियों तक सीमित दिखाई देता है। विद्यार्थियों के व्यवहार एवं दृष्टिकोण में अपेक्षित परिवर्तन सुनिश्चित करने हेतु अनुभवात्मक एवं जीवन–संबंधी शिक्षण विधियों का पर्याप्त उपयोग अभी भी सीमित है। इससे नैतिक शिक्षा एवं दैनिक जीवन के मध्य अपेक्षित संबंध स्थापित नहीं हो पाता।
- डिजिटल युग ने नैतिक शिक्षा के स्वरूप को भी प्रभावित किया है। सामाजिक मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डिजिटल संचार के बढ़ते उपयोग ने नए नैतिक प्रश्नों को जन्म दिया है, जैसेकृडिजिटल नागरिकता, गोपनीयता, ऑनलाइन आचरण एवं सूचना की प्रामाणिकता। इन परिस्थितियों में नैतिक शिक्षा का दायरा पारंपरिक विषयों से आगे बढ़कर डिजिटल नैतिकता एवं वैश्विक उत्तरदायित्व तक विस्तारित हो गया है। भारतीय शिक्षा प्रणाली के समक्ष यह एक नई एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में उभरकर सामने आई है।
- भारतीय समाज की विविधता भी नैतिक शिक्षा को एक विशिष्ट संदर्भ प्रदान करती है। भाषा, संस्कृति, धर्म एवं जीवन–शैली की विविधता के मध्य ऐसे सार्वभौमिक मूल्यों की पहचान एवं संवर्धन आवश्यक है, जो सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ कर सकें। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है, क्योंकि यह भारतीयता एवं वैश्विक दृष्टिकोण के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है।

समग्र रूप से देखा जाए, तो भारत में नैतिक शिक्षा के लिए संस्थागत आधार एवं नीतिगत समर्थन उपलब्ध है, किंतु इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शिक्षण पद्धतियों, शिक्षक–प्रशिक्षण एवं संस्थागत संस्कृति में निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।

चुनौतियाँ–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नैतिक मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किए जाने के बावजूद, इनके प्रभावी क्रियान्वयन के समक्ष अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। ये चुनौतियाँ संरचनात्मक, शैक्षणिक एवं सामाजिक स्तरों पर परिलक्षित होती हैं और मूल्य–आधारित शिक्षा की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। इसकी प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित बिन्दुओं में स्पश्ट की गयी हैं–

- प्रथम, शिक्षा का बढ़ता व्यावसायीकरण नैतिक शिक्षा के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अनेक संस्थानों में शैक्षणिक सफलता को परीक्षा परिणामों एवं रोजगारोन्मुख उपलब्धियों के आधार पर मापा जाता है, जिसके कारण मूल्य–आधारित अधिगम को अपेक्षित प्राथमिकता प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसी परिस्थितियों में नैतिक विकास शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों से क्रमशः पृथक होता दिखाई देता है।

- द्वितीय, शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित सीमाएँ भी उल्लेखनीय हैं। नैतिक मूल्यों का विकास केवल सैद्धांतिक ज्ञान से संभव नहीं हैय इसके लिए शिक्षकों में उपयुक्त दृष्टिकोण, संवेदनशीलता एवं व्यवहारिक कौशल का होना आवश्यक है। वर्तमान समय में सभी शिक्षकों को मूल्य–आधारित शिक्षण की प्रभावी पद्धतियों का पर्याप्त प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं हो पाता, जिससे नीति के उद्देश्यों का पूर्ण क्रियान्वयन प्रभावित होता है।
- तृतीय, सामाजिक एवं पारिवारिक परिवेश में हो रहे परिवर्तन भी नैतिक शिक्षा को प्रभावित करते हैं। एकल परिवारों की बढ़ती संख्या, समयाभाव एवं डिजिटल माध्यमों पर बढ़ती निर्भरता के कारण बच्चों एवं युवाओं के सामाजिककरण की प्रक्रिया में परिवर्तन आया है। परिणामस्वरूप, परिवार एवं समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से प्रदान किए जाने वाले अनेक नैतिक अनुभवों की उपलब्धता सीमित हुई है।
- चतुर्थ, मूल्यांकन प्रणाली में नैतिक विकास को मापने की स्पष्ट एवं मानकीकृत व्यवस्था का अभाव भी एक चुनौती है। संज्ञानात्मक उपलब्धियों का मूल्यांकन अपेक्षाकृत सरल होता है, किंतु सहानुभूति, ईमानदारी एवं सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे गुणों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जटिल प्रक्रिया है। इस कारण नैतिक शिक्षा के परिणामों का समुचित आकलन करना कठिन हो जाता है।
- पंचम, डिजिटल युग में सूचना की तीव्रता एवं विविधता ने नई नैतिक चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। मिथ्या सूचना, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन असहिष्णुता एवं डिजिटल व्यसन जैसी समस्याएँ विद्यार्थियों के व्यवहार एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए पारंपरिक नैतिक शिक्षा के साथ–साथ डिजिटल नैतिकता को भी शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित करना आवश्यक हो गया है।
- षष्ठम, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के मध्य संसाधनों एवं अवसरों की असमानता भी नीति के समान क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों, सरकारी एवं निजी संस्थानों तथा विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य विद्यमान अंतर मूल्य–आधारित कार्यक्रमों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

इन चुनौतियों से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केवल नीतिगत घोषणाएँ पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि इनके समर्थन में सुदृढ़ संस्थागत तंत्र, प्रशिक्षित मानव संसाधन एवं सामाजिक सहयोग की भी आवश्यकता है।

संभावनाएँ एवं नीतिगत सुझाव–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मूल्य–आधारित शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अनेक संभावनाएँ प्रस्तुत करती है। यदि इसके प्रावधानों को योजनाबद्ध एवं समन्वित रूप से क्रियान्वित किया जाए, तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में नैतिक चेतना एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को अधिक प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है।

- प्रथम, विद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर नैतिक शिक्षा के लिए अंतर्विषयक पाठ्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए। इन पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान परंपरा, संवैधानिक मूल्यों, डिजिटल नैतिकता एवं वैश्विक नागरिकता जैसे विषयों को समाविष्ट किया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों को नैतिक प्रश्नों की बहुआयामी समझ विकसित करने में सहायता मिलेगी।
- द्वितीय, शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मूल्य–आधारित शिक्षण को अनिवार्य घटक के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। शिक्षकों को संवादात्मक, अनुभवात्मक एवं सहभागितापूर्ण शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है, ताकि वे विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी संवर्धन कर सकें।
- तृतीय, शैक्षणिक संस्थानों में सामुदायिक सेवा एवं सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्थानीय समुदायों के साथ कार्य करने के अवसर विद्यार्थियों में सहानुभूति, नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व जैसे गुणों का विकास करने में सहायक हो सकते हैं। इस प्रकार की गतिविधियाँ शिक्षा को व्यवहारिक एवं समाजोपयोगी स्वरूप प्रदान करती हैं।
- चतुर्थ, डिजिटल नैतिकता एवं मीडिया साक्षरता को पाठ्यचर्या में स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन व्यवहार, सूचना के सत्यापन एवं डिजिटल उत्तरदायित्व से संबंधित ज्ञान अत्यंत आवश्यक हो गया है। इससे वे डिजिटल परिवेश में अधिक सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम हो सकेंगे।
- पंचम, नैतिक शिक्षा के मूल्यांकन हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए। आत्म–मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन एवं प्रेक्षण आधारित विधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के नैतिक एवं सामाजिक विकास का अधिक समग्र आकलन किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण मूल्यांकन को अधिक मानवीय एवं संदर्भपरक बनाने में सहायक होगा।

अंततः, नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार, शैक्षणिक संस्थानों, परिवार एवं नागरिक समाज के मध्य सहयोग को सुदृढ़ करना आवश्यक है। मूल्य–आधारित शिक्षा तभी सफल हो सकती है, जब समाज के विभिन्न घटक समान उद्देश्यों एवं साझा उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें।

निष्कर्ष–

नैतिक मूल्य एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का संबंध भारतीय शिक्षा व्यवस्था के भविष्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा को अधिक समग्र, मानवीय एवं उत्तरदायी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण वैचारिक आधार प्रदान किया है। नीति में निहित प्रावधान केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे चरित्र निर्माण, सामाजिक समरसता एवं संवैधानिक मूल्यों के संवर्धन की भी परिकल्पना करते हैं। नैतिक मूल्यों का विकास किसी एक पाठ्यक्रम, विषय अथवा गतिविधि के माध्यम से संभव नहीं है। इसके लिए ऐसी शैक्षिक संस्कृति की आवश्यकता होती है, जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी, परिवार एवं समाज समान रूप से सहभागी हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है, किंतु इसकी सफलता प्रभावी क्रियान्वयन, सतत मूल्यांकन एवं संस्थागत प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी। यदि शिक्षा को ज्ञान एवं नैतिकता के समन्वित स्वरूप में विकसित किया जाता है, तो वह न केवल सक्षम मानव संसाधन का निर्माण करेगी, बल्कि ऐसे नागरिकों को भी तैयार करेगी, जो लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय एवं मानव कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध हों। यही दृष्टिकोण भारत को एक अधिक समावेशी, संवेदनशील एवं प्रगतिशील समाज के निर्माण की दिशा में अग्रसर कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

Government of India (2020) National Education Policy 2020, Ministry of Education.
University Grants Commission (2023) Guidelines on Human Values and Professional Ethics.
NCERT (2005) National Curriculum Framework.
UNESCO (2021) Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education.
Delors, J. (1996) Learning: The Treasure Within, UNESCO.
Kothari Commission (1966) Education and National Development.
Gandhi, M. K. (1953) Basic Education.
Vivekananda, Swami (1998) The Complete Works of Swami Vivekananda.
NITI Aayog (2024) India SDG Report.
Ministry of Education (2024) Annual Report.
Ministry of Electronics and Information Technology (2023) Digital India Report.
UNDP (2024) Human Development Report.